(Authoritative English Text of this Department's Notification No. Rev-D (G) 6-12/2016, dated 31-07-23 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Revenue

No. Rev-D (G)6-12/2016 Dated-Shimla-171002 31- 07-2023

NOTIFICATION

Whereas, the draft Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 2023 were published in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh dated 26-04-2023 for inviting objections and suggestions from the general public vide this Department's notification of even number dated 25-04-2023 as required under sub-section (3) of section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974, (Act No. 18 of 1974) read with sub-section (2) of section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973);

And whereas, the objection (s) and suggestions (s) so received in this behalf have been duly considered and rejected;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) read with section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013 notified vide this Department's notification No. Rev-D (G)6-69/2011 Part-III, dated 04-03-2014 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh dated 05-03-2014, namely:-

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh.

Amendment of rule 7

2. In rule 7 of the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013, for the first proviso the following shall be substituted, namely:-

"Provided that the State Government shall not grant the lease of land in any case for a period exceeding 40 years.":

By Order

Onkar Chand Sharma
Principal Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh.

..2/-

(30)

Endst. No. No. Rev-D (G)6-12/2016 Dated. Shimla-2 the 31-07-2023

1. All the Administrative Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Principal Secretary to the Chief Minister, HP Shimla-2.
3. The LR-cum-Secretary (Law) to the Government of HP Shimla-2.
4. The Secretary to Governor, HP Shimla-2.
5. All the Head of Departments in H.P
6. All the Divisional Commissioner in HP.
7. All the Deputy Commissioners in HP.
8. All the Sub-Divisional Officer (Civil) in HP.
9. All Tehsildars / Naib Tehsildars posted in Tehsils / Sub-Tehsils, in HP.
10. Clerk of Court to the F.C (Appeal), Govt. of HP. Shimla-2.
11. The Controller, Printing and Stationery, HP. Government Press, Shimla-5 for publication in the HP Government Gazette (Extraordinary) Five copies of the gazette may kindly be sent to this Department for record.
12. Guard File.

(Balwan Chand)
Joint Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh

(311)

हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग।

सख्याः रैव डी (जी) 6–12/2016 तारीख शिमला –171002 31- 07–2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2023 के प्रारूप को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 25–04–2023 द्वारा, हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 की उप–धारा(2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 13 की उप–धारा(3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जन साधारण से आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए 26–04–2023 को राजपत्र(ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित्त प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) और सुझाव (सुझावों) पर सम्यक् रूप से विचार किया गया और उन्हें अस्वीकृत किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू–जोत, अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः रैव–डी (जी) 6–69/2011–पार्ट III तारीख 4–03–2014 द्वारा अधिसूचित और तारीख 05–03–2014 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है; अर्थातः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र(ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

नियम 7 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 के नियम 7 में, पहले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

''परन्तु राज्य सरकार किसी भी दशा में 40 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर भूमि प्रदान नहीं करेगी।''

आदेश द्वारा,

(ओंकार चंद शर्मा)
प्रधान सचिव (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

..2/–

पृष्ठांकन संख्याः – रैव–डी0(जी0)6–12/2016 तारीखः शिमला–2, 31– 07–2023

प्रतिलिपि प्रेषित हैः–

1. समस्त सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
2. समस्त मण्डलाधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
4. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
5. समस्त उप–मण्डलाधिकारी(ना0), हिमाचल प्रदेश ।
6. सहायक विधि परामर्शदाता एवं सचिव(विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार ।
7. समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, हिमाचल प्रदेश जो उप तहसीलों में कार्यरत हैं।
8. क्लर्क आफ कोर्ट, वित्तायुक्त(अपील), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
9. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, शिमला–5 को राजपत्र(असाधारण) में प्रकाशन हेतु इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वह राजपत्र की पांच प्रतियां विभाग के रिकार्ड हेतु प्रेषित करें ।
10. गार्ड फाईल।

(बलवान चंद)
संयुक्त सचिव(राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार।